भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4394

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

तेलंगाना में पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना

4394. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः

श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेलंगाना सरकार ने पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है क्योंकि इसमें राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों और 12 लाख एकड़ से अधिक सिंचित भूमि को जल की आपूर्ति करने के अलावा पेयजल और औद्योगिक क्षेत्र के लिए जल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): तेलंगाना सरकार द्वारा पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना को एक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है। हालांकि, किसी भी परियोजना को केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा उस परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और उसके बाद जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा इस परियोजना की स्वीकृति, इस मंत्रालय की चल रही योजनाओं में शामिल किए जाने पर आगे विचार करने के लिए एक आवश्यक पूर्वापेक्षा है। सितंबर 2022 में, तेलंगाना सरकार द्वारा पलामारु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत कर दी गई है। चूंकि पलामारु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना में कृष्णा नदी के पानी का उपयोग शामिल है और इस परियोजना के अंतर-राज्यीय पहलू कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II के विचारार्थ विषयों में शामिल हैं, इसलिए यह मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है और अभी पलामारु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। परियोजना के प्रस्ताव को दिसंबर 2024 में तेलंगाना सरकार को वापस कर दिया गया है।

*****